

रेशम उत्पादन से ग्रामीण परिवारों में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन एक वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध-पत्र - ग्रामीण समाज शास्त्र, कृषि-अर्थशास्त्र और लैंगिक अध्ययन के अंतर्विषयी परिप्रेक्ष्य में

डॉ. आशुतोष

सहायक आचार्य, ईश्वरी प्रसाद रामकली देवी महाविद्यालय, ग्राम विरासिन, पोस्ट निगोही,
जनपद शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश - 242407

सारांश

रेशम उत्पादन ग्रामीण भारत में कृषि, कुटीर उद्योग और परिवार-आधारित श्रम का ऐसा संगम है, जिसमें पोषक वृक्षों की खेती से लेकर कीटपालन, कोकून उत्पादन, रीलिंग, कताई, बुनाई और विपणन तक कई प्रक्रियाएँ शामिल हैं। इस शोध-पत्र का उद्देश्य यह है कि इस आजीविका से ग्रामीण परिवारों की आय, रोजगार, लैंगिक भूमिका, शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्णय-निर्माण, सामाजिक प्रतिष्ठा और सामुदायिक सहभागिता में क्या बदलाव आता है। 2020 से 2025 के बीच प्रकाशित सरकारी प्रतिवेदनों, योजना-दस्तावेजों और सहकर्मी-समीक्षित अध्ययनों का विषयगत संश्लेषण अध्ययन में वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक है। उपलब्ध प्रमाण दर्शाते हैं कि रेशम उत्पादन अल्पसंख्यक और सीमांत कृषकों को पूरक आय, वर्ष के भीतर बार-बार काम और परिवार के निकट काम दे सकता है। इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ती है, लेकिन यह अपने आप आय पर नियंत्रण, सार्वजनिक गतिशीलता, परिसंपत्ति स्वामित्व या स्वतंत्र निर्णय क्षमता में बदल नहीं जाता। जब परिवारों को गुणवत्तापूर्ण बीज, तकनीकी प्रशिक्षण, रोग नियंत्रण, सस्ती पूँजी, पारदर्शी कोकून बाजार, उत्पादक समूह और मूल्य-संवर्धन की सुविधाएँ मिलती हैं, तो सामाजिक लाभ अधिक स्पष्ट होते हैं। इसके विपरीत, परिवर्तन को मूल्य-अस्थिरता, बीमारी, जलवायु जोखिम, बिचौलिया-निर्भरता, महिलाओं की दोहरी कार्य-भूमिका और संस्थागत पहुँच की असमानता सीमित करती है। शोध-पत्र का मत है कि रेशम उत्पादन को केवल उत्पादन-वृद्धि कार्यक्रम के रूप में नहीं चलाना चाहिए; इसके बजाय, इसे परिवार-केंद्रित सामाजिक विकास, कौशल-विकास, लैंगिक न्याय और स्थानीय मूल्यों के साथ मिलकर चलाना चाहिए।

मुख्य शब्द: रेशम उत्पादन, ग्रामीण परिवार, सामाजिक परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण, आजीविका-सुरक्षा, सामाजिक गतिशीलता

1. भूमिका

आय बढ़ने से ही ग्रामीण परिवारों में सामाजिक परिवर्तन नहीं होता है। इसमें परिवार के सदस्यों की भूमिका, संसाधनों पर अधिकार, निर्णय लेने की क्षमता, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च, सामाजिक प्रतिष्ठा, संस्थागत संपर्क और समुदाय में भागीदारी के बदलते रूप शामिल हैं। परिवार के कई सदस्य अलग-अलग चरणों में योगदान दे सकते हैं, इसलिए रेशम उत्पादन व्यापक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश उत्पादन खेत, घर और आसपास के गाँवों में होता है।

Published: 27 July 2026

DOI: <https://doi.org/10.70558/SPIJSH.2026.v3.i7.45840>

Copyright © 2026 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

इसलिए, इसका प्रभाव सामाजिक संबंधों, श्रम-विभाजन और आर्थिक लाभ पर भी पड़ता है। अल्टमैन और कैरेल, 2022; रेड्डी एवं परशुरामुडु (2024) ने बताया कि भारत में रेशम उत्पादन और रोजगार के कारण क्षेत्र का राष्ट्रीय महत्व है। 2022–23 में देश का कच्चा रेशम उत्पादन 36,582 मीट्रिक टन था, जो पिछले वर्ष से 4.8 प्रतिशत अधिक था, केंद्रीय रेशम बोर्ड ने बताया। इस वर्ष रेशम उद्योग ने 92 लाख लोगों को काम दिया। ये आंकड़े केवल उद्योग का आकार नहीं दिखाते हैं; वे बताते हैं कि ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण परिवारों की आजीविका रेशम मूल्य-श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा है। राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार और उत्पादन की वृद्धि को सामाजिक परिवर्तन का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मानना उचित होगा (Central Silk Board, 2024)। परिवार की आय बढ़ सकती है, लेकिन वह समान नहीं हो सकती; महिलाओं का श्रम बढ़ सकता है, लेकिन उनकी निर्णय-क्षमता नहीं बदल सकती; नौकरी मिल सकती है, लेकिन बाजार मूल्य में गिरावट से पैसा सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए इस अध्ययन में परिणामों का मूल्यांकन आय, नियंत्रण, क्षमता, सुरक्षा और प्रतिष्ठा जैसे परस्पर संबंधित आयामों पर किया गया है। रॉय एवं रॉय मुखर्जी, 2020; 1.1 अध्ययन की समस्या: रेशम उत्पादन को अक्सर ग्रामीण रोजगार और महिला-अनुकूल उद्यम के रूप में चित्रित किया जाता है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों के प्रमाण समान नहीं हैं। विभिन्न अध्ययनों में कम शिक्षा, प्रशिक्षण, मूल्य-अस्थिरता और सीमित गतिशीलता ने सामाजिक लाभों को बाधित किया है, जबकि कुछ अध्ययनों में परिवार की नियमित आय और निर्णय-भागीदारी में सुधार देखा गया है। मुख्य शोध-समस्या यह है कि रेशम उत्पादन किन तंत्रों से सामाजिक परिवर्तन पैदा करता है और किन परिस्थितियों में यह परिवर्तन सीमित, असमान या अस्थायी रहता है। (हतीबरुआ, २०२२; Bhattacharyya et al., 2020; 1.2 अध्ययन का उद्देश्य: रेशम उत्पादन और ग्रामीण परिवारों की आय, रोजगार और आजीविका-सुरक्षा के बीच संबंध का विश्लेषण करना। (Ahmad and Fatimah, 2025)

- महिलाओं की श्रम-भागीदारी, आय पर नियंत्रण, निर्णय लेने की क्षमता और सार्वजनिक सहभागिता में होने वाले बदलाव को समझना
- शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन-स्तर, सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक संबंधों पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों का विश्लेषण करना
- बाजार, धन, प्रशिक्षण, तकनीक, बीमारी, जलवायु और सरकारी सहायता से जुड़े अवरोधों का पता लगाना
- परिवार-केंद्रित और समावेशी रेशम विकास के लिए व्यावहारिक सुझाव देना

1.3 शोध प्रश्न: क्या रेशम उत्पादन से ग्रामीण परिवारों को स्थिर आय मिलती है?

- वास्तविक सशक्तिकरण में महिलाओं की अधिक श्रम-भागीदारी किस सीमा तक बदलती है?
- शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और सामाजिक प्रतिष्ठा में रेशम उत्पादन से क्या लाभ मिलता है?
- क्या संस्थागत और आर्थिक बाधाएं अपेक्षित सामाजिक लाभों को सीमित करती हैं?

2. रेशम उत्पादन की अवधारणा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसका महत्व

रेशम बनाने में कई जैविक और औद्योगिक प्रक्रियाएं शामिल हैं। इसमें शहतूत या वन-आधारित पोषक वृक्षों की स्थापना, रोग-मुक्त अंडों की उपलब्धता, कीटपालन, कोकून उत्पादन, रीलिंग, सूत बनाना, रंगना, बुनाई और विपणन शामिल हैं। इस बहु-स्तरीय संरचना के कारण खेती, पशु-जैसी देखभाल, सूक्ष्म प्रसंस्करण और हस्तकौशल एक ही मूल्य-श्रृंखला में शामिल हैं। भूमि, श्रम, पारंपरिक ज्ञान और समय के अनुसार, ग्रामीण परिवार इसके एक या अधिक चरणों में भाग ले सकते हैं। (Central Silk Board, 2022; अल्टमैन और कैरेल (2022), रेशम उत्पादन

में दो विशेषताएं हैं: श्रम-गहनता और गतिविधियों की आवृत्ति। शहतूत की पत्ती उत्पादन और कीटपालन के लिए नियमित देखभाल आवश्यक है, ताकि कृषि के खाली समय में भी काम मिल सके। घर के निकट कार्यक्रमों में वृद्ध और महिलाओं की भागीदारी की संभावना अधिक होती है, जबकि रीलिंग, कटाई और बुनाई जैसे गैर-कृषि कौशलों के लिए अवसर मिलते हैं। रेशम उत्पादन कृषि और गैर-कृषि आय को ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में जोड़ सकता है। होसामनी और अन्य, २०२०; Reddy and Parsurambudu, 2024) के अनुसार, शहतूत-आधारित प्रणालियाँ दीर्घजीवी पौधों, पत्तियों की बार-बार कटाई और उप-उत्पादों का पुनः उपयोग करने की क्षमता प्रदान करती हैं। वन-आधारित तसर, एरी और मूगा प्रणालियाँ आदिवासी आजीविका और विशिष्ट पारिस्थितिक क्षेत्रों से संबंधित हैं। पारिस्थितिक लाभ स्वयं नहीं मिलते; उनकी दिशा रासायनिक उपयोग, जल प्रबंधन, रोग नियंत्रण और जैव-विविधता संरक्षण से निर्धारित होती है। अल्टमैन और फैरेल, 2022; Mishra, 2021)

तालिका 1. रेशम उत्पादन से सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख आयाम

आयाम	मुख्य तंत्र	संभावित सकारात्मक परिवर्तन	मुख्य जोखिम
आर्थिक	कोकून और प्रसंस्कृत उत्पाद की बिक्री	आय-विविधीकरण, नकद प्रवाह, बचत	मूल्य-अस्थिरता, रोग और ऋण
रोजगार	परिवार-आधारित एवं स्थानीय श्रम	मौसमी बेरोजगारी में कमी, कौशल-विकास	अनौपचारिकता, कम मजदूरी, कार्य-दबाव
लैंगिक	महिलाओं की उत्पादन और विपणन भागीदारी	आय-योगदान, निर्णय-भागीदारी, पहचान	अवैतनिक श्रम, आय पर सीमित नियंत्रण
मानवीय विकास	आय का शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास में उपयोग	विद्यालय निरंतरता, उपचार-सुलभता, बेहतर जीवन-स्तर	कम आय या संकट में व्यय का स्थगन
सामाजिक	समूह, सहकारिता, प्रशिक्षण और बाजार-संपर्क	सामुदायिक नेटवर्क, नेतृत्व, प्रतिष्ठा	समूहों में असमान प्रतिनिधित्व, बिचौलिया नियंत्रण
अंतरपीढ़ीगत	कौशल और परिसंपत्ति का हस्तांतरण	स्थानीय उद्यमिता, युवाओं के लिए अवसर	कम लाभ होने पर युवाओं का पलायन

स्रोत: 2020–2025 के चयनित अध्ययनों के आधार पर विषयगत संश्लेषण।

3. ग्रामीण परिवारों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि

सामाजिक और आर्थिक रूप से शम उत्पादन से जुड़े परिवार एकरूप नहीं हैं। असम के जोरहाट और माजुली क्षेत्र में किए गए अध्ययन में अधिकांश भागीदार अल्पसंख्यक परिवारों से थे; 61.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं की परिचालन जोत 1 हेक्टेयर से कम थी। शिक्षा, प्रशिक्षण, विस्तार-संपर्क और जोखिम वहन क्षमता भी मध्यम या सीमित थीं। रेशम उत्पादन में प्रवेश करने वाले बहुत से परिवार पहले से ही संसाधन-अभाव और कृषि जोखिम का सामना कर

रहे हैं। रेशम उत्पादन की प्रकृति भूमि का आकार से प्रभावित होती है (हतीबरुआ, 2022)। शहतूत-आधारित उत्पादन में पत्ती की नियमित उपलब्धता आवश्यक है, जिससे भूमि और सिंचाई वाले परिवार अधिक चक्र चला सकते हैं। दूसरी ओर, मूगा, तसर और एरी की प्रणालियाँ स्थानीय वन, सामुदायिक संसाधन और पोषक वृक्षों पर निर्भर हो सकती हैं। आदिवासी क्षेत्रों में तसर उत्पादन केवल पैसे का साधन नहीं है; यह पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान और सामुदायिक श्रम-संबंधों से भी जुड़ा हुआ है। Mishra, 2021; केंद्रीय रेशम बोर्ड (2024) के अनुसार, अवसर जाति, जनजातीय स्थिति, लैंगिक मानदंड और भौगोलिक दूरी पर भी निर्भर करते हैं। बाजार से दूर रहने वाले परिवार को परिवहन और जानकारी की अधिक लागत देनी पड़ती है। महिलाओं की घरेलू जिम्मेदारियाँ उन्हें घर-आधारित चरणों में अधिक केंद्रित कर सकती हैं, लेकिन कोकून बाजार, बैंक या प्रशिक्षण केंद्र तक जाने की स्वतंत्रता सीमित हो सकती है। इसलिए, अलग-अलग परिवारों में एक समान उत्पादन कार्यक्रम के अलग-अलग सामाजिक परिणाम हो सकते हैं। (Roy and Roy Mukherji, 2020; हमद और फातिमा, 2025) एकल फसल पर निर्भरता कम करना अक्सर ग्रामीण परिवारों को रेशम उत्पादन के प्रति आकर्षित करता है। फिर भी गरीब परिवार लाभकारी पैमाने तक नहीं पहुँच पाते, अगर वे प्रारंभिक पौध सामग्री, पालन-कक्ष, उपकरण और कार्यशील धन नहीं पाते। ऐसी परिस्थितियों में, उन परिवारों को जो पहले से भूमि, संपर्क या सह-वित्त की क्षमता रखते हैं, वे अधिक संभावना है कि सहायता-योजना का लाभ उठा सकें। यह चयनात्मक पहुँच सामाजिक असमानता को कम करने के बजाय पुनरुत्पादित भी कर सकती है, इसलिए लाभार्थी चयन और अनुवर्ती सहायता में न्यायसंगतता आवश्यक है। (Central Textile Board, 2022; Bhatt and others, 2020)

4. रेशम उत्पादन और आय में परिवर्तन

रेशम उत्पादन से आय में तीन बदलाव होते हैं: कृषि आय का विविधीकरण, परिवार के श्रम का उत्पादक उपयोग और मूल्य-श्रृंखला के अगले पड़ावों से अतिरिक्त मूल्य रीलिंग, कटाई, बुनाई या प्रत्यक्ष विपणन से जुड़ने पर आय के स्रोत बढ़ सकते हैं, लेकिन केवल कोकून बेचने वाला परिवार उत्पादन जोखिम और बाजार मूल्य पर अधिक निर्भर रहता है। इसलिए आय का आकार परिवार की मूल्य-श्रृंखला में स्थान निर्भर करता है। होसामनी और अन्य, २०२०; रेड्डी एवं परशुरामुडु, 2024) कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन वृद्धि ग्रामीण मांग और रोजगार के लिए अच्छा संकेत देती है, लेकिन परिवार स्तर पर आय स्थिर नहीं है। 2022-23 में कच्चे रेशम उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन तसर उत्पादन में गिरावट हुई और विभिन्न किस्मों में असमान प्रदर्शन हुआ। इससे राष्ट्रीय औसत स्थानीय खतरों को छिपा सकता है। केंद्रीय रेशम बोर्ड (2024) ने बिहार के चार जिलों में 120 महिलाओं पर आधारित एक अध्ययन में रेशम उत्पादों का घरेलू आय में 28.41% योगदान बताया। नतीजों से पता चलता है कि रेशम उत्पादन पूरक आय से अधिक हो सकता है और परिवार की मुख्य आय का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। हालाँकि, आय का अनुपात रेशम के प्रकार, उत्पादन पैमाने, बाजार-संपर्क और परिवार की अन्य आय पर निर्भर करता है, इसलिए इस निष्कर्ष को क्षेत्र-विशिष्ट मानना चाहिए। (अहमद एवं फातिमा, 2025) परिवार की खपत और सुरक्षा में आय की नियमितता महत्वपूर्ण है। कोकून चक्र को छोटे अंतराल पर पूरा करने से भोजन, दवा, स्कूल और दैनिक खर्चों के लिए पैसे मिल सकते हैं। दूसरी ओर, पूरे चक्र की आय को रोग, खराब अंडे, कम तापमान या अचानक मूल्य-पतन प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि शुद्ध प्रतिफल, जोखिम, श्रम-समय और ऋण-देयता को सकल आय के बजाय एक साथ देखना चाहिए। होसामनी और अन्य, २०२०; (घोनमोडे, 2023) महामारी-काल के एक अध्ययन ने बाजार और परिवहन बाधाओं की गंभीरता को उजागर किया। चयनित उत्तरदाताओं ने कहा कि कोकून के औसत बिक्री-मूल्य के लगभग आधा होने, परिवहन और कर्मचारियों की कमी होने और नकदी के प्रवाह में बाधा होने की रिपोर्ट की। इससे स्पष्ट होता है कि उत्पादन क्षमता कम है; जोखिम साझाकरण, भंडारण, बाजार जानकारी और वैकल्पिक खरीदार की सामाजिक सुरक्षा आवश्यक है। गोमोडे, 2023

5. रेशम उत्पादन और महिला सशक्तिकरण

महिलाओं को घर के निकट काम मिलने से उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ सकती है, खासकर उन इलाकों में जहाँ बाहर जाकर काम करने पर सामाजिक प्रतिबंध हैं। महिला की भागीदारी से घरेलू आय में उसका योगदान दिखाई देता है और परिवार में उसकी उपयोगिता और पहचान बढ़ सकती है। रॉय एवं रॉय मुखर्जी, 2020; मधु एवं अन्य, 2023) कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर जिले में ९० रेशम कृषक परिवारों पर आधारित अध्ययन ने महिला सशक्तिकरण का सूचकांक 0.688 पाया, जबकि पर्याप्त सशक्तिकरण की सीमा 0.75 थी। उस सीमा से ऊपर व्यक्तिगत सशक्तिकरण केवल 22.22% महिलाओं ने दर्ज किया। इस परिणाम का मूल संदेश यह है कि सशक्तिकरण और श्रम-भागीदारी समान नहीं हैं। वास्तविक सशक्तिकरण में शामिल हैं महिलाओं के कार्य का आर्थिक मूल्य, आय पर उनका नियंत्रण, उत्पादन निर्णय, बाजार तक पहुँच और सार्वजनिक अभिव्यक्ति। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले पर एक अध्ययन भी इसी अंतर को दिखाता है (Madhu et al., 2023)। वहाँ महिला-प्रधान श्रम संरचना के बावजूद सशक्तिकरण और उत्पादकता अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँची। उत्पादन बढ़ने पर भी महिलाओं की वार्ताकार शक्ति सीमित रह सकती है क्योंकि वे अधिकतर अवैतनिक पारिवारिक श्रमिक हैं और भूमि, उपकरण, बैंक खाते अथवा बिक्री-निर्णय पर अधिकार नहीं रखतीं। रॉय एवं रॉय मुखर्जी, 2020 के अनुसार, महिला सशक्तिकरण को पाँच स्तरों पर समझना लाभदायक है: नियंत्रण पर समय, नियंत्रण पर आय, नियंत्रण पर घरेलू निर्णय, नियंत्रण पर उत्पादन-संसाधनों और समुदाय में आवाज। रेशम उत्पादन समय और पैसे के अवसर देता है, लेकिन घरेलू काम करने पर कार्यदिवस लंबे हो सकते हैं। पुरुष बाजार और भुगतान पर नियंत्रण रखते हैं, तो महिला का योगदान सांकेतिक रहता है। यही कारण है कि महिलाओं को बैंक भुगतान, संयुक्त परिसंपत्ति, बाजार-यात्रा सहायता, नेतृत्व प्रशिक्षण और बाल-देखभाल प्रदान करने की जरूरत है। (Madhu et al., 2023; (अहमद और फातिमा, २०२५). महिलाओं की शिक्षा और बाहरी गतिशीलता में सबसे बड़ी बाधा बिहार का अध्ययन बताता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभावी होंगे जब वे समय, स्थान, भाषा और व्यावहारिक रूप से महिलाओं के लिए अनुकूल होंगे। महिला प्रशिक्षक, प्रदर्शन इकाई, समूह-आधारित परामर्श और चरणबद्ध मार्गदर्शन एकमात्र प्रशिक्षण के बजाय अधिक लाभदायक हो सकते हैं। (अहमद और फातिमा, २०२५; Central Silk Board, 2022)

6. रोजगार-सृजन और पारिवारिक आजीविका सुरक्षा

रेशम उत्पादन की मूल्य-श्रृंखला के कारण निरंतर श्रम माँग है। पोषक वृक्षों की देखभाल करने के लिए अलग-अलग कौशल और समय-सारिणी की आवश्यकता होती है, जैसे पत्ती संग्रह, कीटपालन, सफाई, चंद्रिका व्यवस्था, कोकून बिक्री, रीलिंग और बुनाई। इससे परिवार के कई सदस्यों को अलग-अलग काम करने का अवसर मिलता है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-रोजगार और मजदूरी दोनों का विकास हो सकता है। इस व्यापक श्रम-अवशोषण क्षमता का प्रमाण राष्ट्रीय रोजगार अनुमान है। (Central Silk Board, 2024; रेड्डी एवं परशुरामुडु (2024) का कहना है कि आजीविका-सुरक्षा का अर्थ केवल काम करने वाले दिनों की संख्या नहीं है, बल्कि आय-स्रोतों की विविधता और संकट से उबरने की क्षमता है। रेशम उत्पादन को खाद्यान्न खेती, पशुपालन या अन्य व्यवसायों में शामिल करने से परिवार किसी एक स्रोत की विफलता से कम प्रभावित होता है। किंतु विविधीकरण का लाभ सीमित हो सकता है अगर सभी गतिविधियाँ जलवायु, ऋण या बाजार संकट से प्रभावित हों। अल्लमैन और फैरेल, 2022; Hosaini et al., 2020) रेशम क्षेत्र में तकनीकी सेवा, उपकरण मरम्मत, बीज वितरण, रोग परीक्षण, डिजिटल बाजार जानकारी, डिजाइन, रंगाई और उत्पाद विपणन जैसे अवसर उभर सकते हैं। इससे कृषि से पूरी तरह से पलायन करने के बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल-आधारित उद्यमिता की शुरुआत हो सकती है। लेकिन कम लाभ, कम मूल्य और कम सामाजिक प्रतिष्ठा क्षेत्र से युवा पीढ़ी को दूर कर सकते हैं। इसलिए उत्पादन प्रशिक्षण के अलावा बाजार-नवाचार और व्यावसायिक योजना भी आवश्यक हैं। (Central Silk Board, 2022; भट्टाचार्य एवं अन्य, 2020) तसर आधारित

क्षेत्रों में आजीविका-सुरक्षा का गहरा संबंध वनाधिकार और पोषक वृक्षों तक पहुँच से है। प्रशिक्षण और बीज सहायता भी दीर्घकालिक परिणाम नहीं देगी अगर समुदायों का संसाधन स्थिर नहीं है। आदिवासी परिवारों के लिए नीतियों को सामुदायिक संस्थाओं, स्थानीय प्रसंस्करण और पारिस्थितिक संरक्षण से जोड़ना चाहिए। मैरी, 2021)

7. शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन-स्तर पर प्रभाव

रेशम उत्पादन शिक्षा पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होता, बल्कि आय और अपेक्षाओं के माध्यम से प्रभावित होता है। नियमित नकदी प्रवाह से शिक्षा, पुस्तकें, परिवहन और डिजिटल शिक्षण उपकरणों पर खर्च हो सकता है। शिक्षा को आर्थिक विकास के साधन के रूप में देखने की प्रवृत्ति भी मजबूत हो सकती है जब परिवार में कौशल और बाजार-संपर्क बढ़ता है। फिर भी क्षेत्रीय अध्ययनों में शिक्षा पर दीर्घकालिक कारणात्मक प्रभाव का बहुत कम अनुगामी प्रमाण है; इसलिए, इस संबंध को परिस्थितिनिष्ठ और संभावित मानना चाहिए। (हतीबरुआ, २०२२; Ahmed and Fatimah, 2025) स्वास्थ्य पर प्रभाव दो तरह से हो सकता है। आय बढ़ने से पोषण, उपचार और स्वच्छ आवास पर खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन कीटपालन की लगातार निगरानी, धुएँ या रसायन का अनुचित उपयोग, गर्म रीलिंग इकाइयाँ और लंबा कार्य-दिवस स्वास्थ्य को खतरा भी बना सकते हैं। महिलाओं को घरेलू और उत्पादक काम करना थकान और समय-अभाव का कारण बन सकता है। इसलिए स्वास्थ्य-जागरूकता और श्रम-सुरक्षा को उत्पादकता प्रशिक्षण से अलग नहीं रखना चाहिए। अल्टमैन और फैरेल, 2022; रॉय एवं रॉय मुखर्जी, 2020) आवास सुधार, घरेलू उपकरण, स्वच्छता, ऊर्जा-सुविधा, भोजन की विविधता और सामाजिक अवसरों में भागीदारी सबसे आम संकेत हैं कि जीवन-स्तर में परिवर्तन होता है। स्थिर आय से निर्मित संपत्ति और ऋण से निर्मित संपत्ति में फर्क है। यदि परिवार को निरंतर बीमारी या धन की कमी का सामना करना पड़े, तो उसे बचत खत्म करनी या परिसंपत्ति बेचनी पड़ सकती है। यही कारण है कि जीवन-स्तर का मूल्यांकन आय के साथ बचत, ऋण और जोखिम-सहन क्षमता को भी शामिल करना चाहिए। होसामनी और अन्य, २०२०; Hoganmode, 2023) रेशम उत्पादन से प्राप्त सामाजिक लाभों का प्रभाव बच्चों पर लैंगिक रूप से अलग हो सकता है। महिलाओं की आय पर वास्तविक नियंत्रण होने पर बालिकाओं की शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया जाएगा; हालाँकि, बालिकाओं को घरेलू रेशम काम में अधिक समय देने से उनकी विद्यालय उपस्थिति प्रभावित हो सकती है। बाल श्रम को प्रतिबंधित करना, शिक्षा की निरंतरता और परिवार के कार्य-दबाव को संतुलित करना चाहिए। (Madhu et al., 2023; (अहमद और फातिमा, २०२५)

8. सामाजिक प्रतिष्ठा, निर्णय-क्षमता और पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन

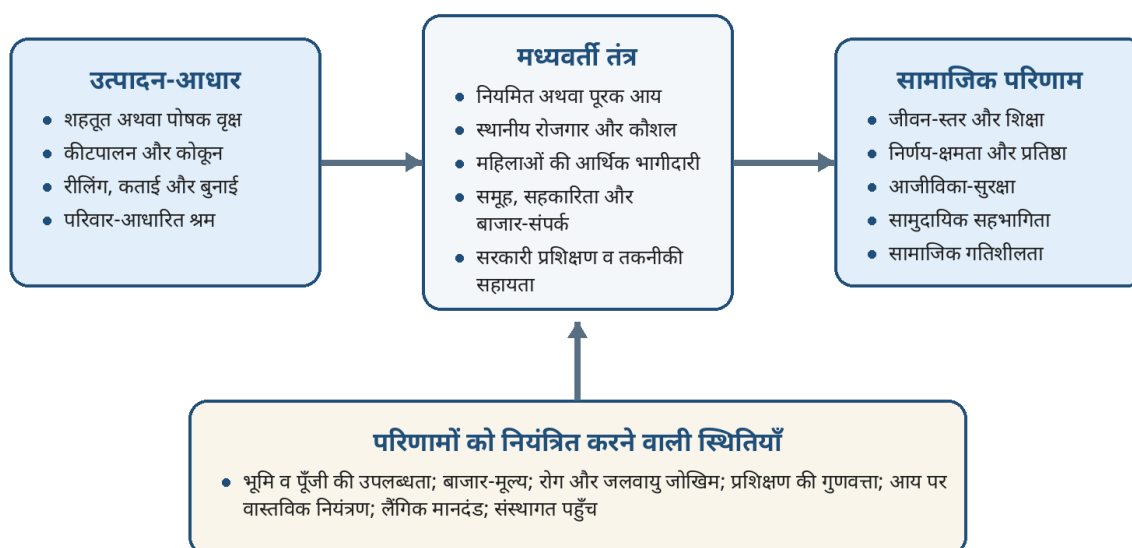
ग्रामीण समाज में आय कमाने से सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है, लेकिन प्रतिष्ठा का स्वरूप स्थानीय नियमों पर निर्भर करता है। सफल कोकून उत्पादक, समूह-पदाधिकारी, स्थानीय खरीदार या प्रशिक्षित महिला सूचना और संसाधन का केंद्र बन सकते हैं। इससे पंचायतों, सहकारी संस्थाओं और दूसरे विकास कार्यक्रमों तक पहुँच बढ़ सकती है। (हतीबरुआ, २०२२; रेड्डी एवं परशुरामुडु, 2024) कहते हैं कि परिवार की निर्णय-क्षमता तीन हिस्सों से बनती है: आय-योगदान, संसाधन-स्वामित्व और ज्ञान। यदि एक महिला पालन-तकनीक और रोग-प्रबंधन में प्रशिक्षित होती है, तो वह उत्पादन निर्णयों में अधिक प्रभावी होती है। यदि व्यक्ति अंतिम बिक्री और भुगतान करता है, तो आर्थिक अधिकार अपूर्ण रहता है। इसलिए बीज खरीद, ऋण, श्रम-नियोजन, बिक्री, आय-उपयोग और बचत के सभी स्तरों पर निर्णय-भागीदारी को मापना चाहिए। (Madhu et al., 2023; रॉय एवं रॉय मुखर्जी, 2020 के अनुसार, रेशम उत्पादन पारिवारिक सहयोग को बढ़ा सकता है क्योंकि एक सफल चक्र के लिए निरंतर समूहिक श्रम आवश्यक है। साथ ही, इससे कार्य-विभाजन, आय-वितरण और ऋण-निर्णय में कठिनाई भी हो सकती है। परिवार में असंतोष बढ़ सकता है अगर महिलाओं और बच्चों का काम अदृश्य माना जाएगा। सामाजिक लाभ स्पष्ट कार्य-विभाजन, पारदर्शी आय लेखा और संयुक्त निर्णय से बढ़ते हैं। रॉय एवं रॉय मुखर्जी, 2020; होसामनी एवं अन्य, 2020 के अनुसार, सामाजिक

गतिशीलता अधिक टिकाऊ होती है जब आय को कौशल, शिक्षा, संगठनात्मक सदस्यता और संपत्ति-निर्माण के साथ जोड़ते हैं। थोड़े से अच्छे उत्पादन चक्र प्रतिष्ठा को कुछ समय के लिए सुधार सकते हैं, लेकिन बाजार संकट इसे उलट सकते हैं। इसलिए सामाजिक परिवर्तन को एक दीर्घकालिक प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए, जिसमें परिवार की क्षमता और संस्थागत संरक्षण दोनों बढ़ते हैं। (भट्टाचार्य और अन्य, २०२०; घोनमोडे, २०३३)

9. ग्रामीण समाज में सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक गतिशीलता

सामूहिकता रेशम उत्पादन में महत्वपूर्ण है। समूह रोग-मुक्त बीज, उपकरण, प्रशिक्षण, परिवहन और बाजार सूचना की लागत कम कर सकता है। गुणवत्ता मानकीकरण, सामूहिक बिक्री और बेहतर बातचीत में उत्पादक समूह और सहकारी संस्थाएँ सहायता कर सकती हैं। यही कारण है कि परिवार की व्यक्तिगत सौदेबाजी सामुदायिक आर्थिक शक्ति बन जाती है। (Central Silk Board, 2022; Bhattacharya et al., 2020) समूह केवल वित्तीय संस्थाएँ नहीं हैं; वे नेतृत्व, पारस्परिक सहायता और सूचना के मंच भी हैं। महिलाएँ नियमित बैठकों से सार्वजनिक बोलने, लेखा रखने, बैंकों और सरकारी कार्यालयों से संपर्क करने का अनुभव प्राप्त कर सकती हैं। यह अनुभव उनकी घरेलू सीमा से बाहर सामाजिक पहचान बनाता है। लेकिन लाभ असमान हो सकता है अगर समूह में वास्तविक भागीदारी न हो और निर्णय कुछ महत्वपूर्ण सदस्यों तक सीमित रहें। (Madhu et al., 2023; हमद और फातिमा, 2025) कहते हैं कि पारंपरिक रेशम क्षेत्रों में उत्पादित सांस्कृतिक पहचान है। तसर और मूगा जैसे रेशम स्थानीय कला और वेशभूषा का एक हिस्सा हैं। स्थानीय ब्रांडिंग, भौगोलिक पहचान और गुणवत्ता को बाजार से जोड़ने पर सांस्कृतिक पूँजी का अर्थ बदल सकता है। अत्यधिक व्यावसायीकरण पारंपरिक विविधता और स्थानीय नियंत्रण पर भी दबाव डाल सकता है। मैरी, 2021; सामुदायिक गतिशीलता का एक और लाभ ज्ञान-प्रसार है (Althman and Farell, 2022)। प्रशिक्षित किसान आसपास के लोगों के लिए प्रदर्शनकर्ता बन सकते हैं, जिससे नवाचार तेजी से फैलता है। असम में किए गए अध्ययन से पता चलता है कि विस्तार संपर्क और प्रशिक्षण की सीमित पहुँच से समुदाय-आधारित प्रशिक्षक और स्थानीय प्रदर्शन इकाइयाँ औपचारिक संस्थाओं से दूरी कम कर सकते हैं। हतीबरुआ, 2022 में

चित्र 1. रेशम उत्पादन और ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन की अवधारणात्मक रूपरेखा



स्रोत: चयनित साहित्य के आधार पर निर्मित विश्लेषणात्मक रूपरेखा।

10. चुनौतियाँ: बाजार, प्रशिक्षण, पूँजी, तकनीक और सरकारी सहायता

10.1 बाजार और मूल्य-अस्थिरता

कोकून शीघ्र विक्रय की आवश्यकता और सीमित खरीदार परिवारों की सौदेबाजी शक्ति घटाते हैं। गुणवत्ता परीक्षण अस्पष्ट हो, बाजार दूर हो या समय पर मूल्य सूचना न मिले, तो बिचौलिया-निर्भरता बढ़ती है। महामारी-काल ने दिखाया कि परिवहन अवरोध और खरीदारों की अनुपस्थिति मूल्य को तेजी से गिरा सकती है। स्थानीय नीलामी, डिजिटल मूल्य सूचना, सामूहिक परिवहन और न्यूनतम जोखिम-साझाकरण व्यवस्था इस असुरक्षा को घटा सकती है। (घोनमोडे, 2023; केंद्रीय रेशम बोर्ड, 2022)

10.2 प्रशिक्षण और विस्तार

रेशम उत्पादन जैविक रूप से संवेदनशील है; तापमान, आर्द्रता, स्वच्छता और रोग-नियंत्रण में छोटी त्रुटि भी चक्र को प्रभावित कर सकती है। असम के अध्ययन में केवल 42.50 प्रतिशत किसानों को प्रशिक्षण का अनुभव था। एकमुश्त प्रशिक्षण के बजाय मौसम-विशिष्ट परामर्श, खेत-स्तरीय प्रदर्शन, रोग-निदान और मोबाइल सूचना की संयुक्त व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी। (हतीबरुआ, 2022; केंद्रीय रेशम बोर्ड, 2022)

10.3 पूँजी और वित्तीय समावेशन

पालन-कक्ष, उपकरण, पौध सामग्री और कार्यशील पूँजी के लिए वित्त चाहिए। छोटे परिवार प्रायः अनौपचारिक ऋण लेते हैं, जिससे बाजार संकट में ऋण-भार बढ़ सकता है। योजना-अनुदान उपयोगी है, पर सह-वित्त, दस्तावेज और अग्रिम भुगतान जैसी शर्तें कमजोर परिवारों को बाहर कर सकती हैं। सरल ऋण, उत्पादन-चक्र के अनुरूप पुनर्भुगतान, बीमा और समूह-आधारित वित्त आवश्यक हैं। (होसामनी एवं अन्य, 2020; केंद्रीय रेशम बोर्ड, 2022)

10.4 तकनीक, रोग और जलवायु

गुणवत्तापूर्ण बीज और वैज्ञानिक पालन उत्पादकता के आधार हैं। तापमान की चरम स्थितियाँ, अनियमित वर्षा और पत्ती-गुणवत्ता में परिवर्तन जोखिम बढ़ाते हैं। तकनीक को स्थानीय जलवायु, रेशम की किस्म और परिवार की संसाधन-क्षमता के अनुसार अनुकूलित करना चाहिए। महँगे उपकरण बिना मरम्मत सेवा और प्रशिक्षण के निष्प्रभावी हो सकते हैं। (अल्टमैन एवं फैरेल, 2022; भट्टाचार्य एवं अन्य, 2020)

10.5 लैंगिक बाधाएँ

महिलाओं की समय-गरीबी, संपत्ति पर सीमित अधिकार, बाहर जाने की बाधा और प्रशिक्षण तक असमान पहुँच रेशम उत्पादन के सामाजिक लाभ को सीमित करती है। महिला-केंद्रित योजना का अर्थ केवल लाभार्थी सूची में नाम जोड़ना नहीं, बल्कि भुगतान, परिसंपत्ति, बाजार-संपर्क और नेतृत्व पर वास्तविक अधिकार देना है। (मधु एवं अन्य, 2023; अहमद एवं फातिमा, 2025)

तालिका 2. चयनित अध्ययनों से प्राप्त प्रमुख प्रमाण

स्रोत और क्षेत्र	मुख्य प्रमाण	सामाजिक व्याख्या
हतीबरुआ (2022), असम	अधिकांश सीमांत किसान; प्रशिक्षण 42.50%; निर्णय-क्षमता प्रायः मध्यम	लाभ के लिए प्रशिक्षण और विस्तार-संपर्क निर्णायक हैं।

स्रोत और क्षेत्र	मुख्य प्रमाण	सामाजिक व्याख्या
रॉय एवं रॉय मुखर्जी (2020), पश्चिम बंगाल	महिला-प्रधान श्रम के बावजूद उत्पादकता और सशक्तिकरण अपेक्षित स्तर से कम	भागीदारी को संसाधन-अधिकार और आय-नियंत्रण से जोड़ना आवश्यक है।
मधु एवं अन्य (2023), कर्नाटक	90 परिवार; महिला सशक्तिकरण सूचकांक 0.688; 22.22% पर्याप्त स्तर पर	श्रम-भागीदारी सशक्तिकरण की आवश्यक, पर अपर्याप्त शर्त है।
अहमद एवं फातिमा (2025), बिहार	120 महिलाएँ; आय योगदान का अनुमान 28.41%; शिक्षा और गतिशीलता की बाधाएँ	घर-आधारित अवसर आय बढ़ाते हैं, पर बाजार-पहुँच सीमित रह सकती है।
घोनमोडे (2023), महामारी-काल	मूल्य, परिवहन, श्रम और नकदी-प्रवाह में गंभीर बाधा	मूल्य-श्रृंखला के झटकों से सामाजिक लाभ शीघ्र उलट सकते हैं।
केंद्रीय रेशम बोर्ड (2024), भारत	2022-23 में 36,582 मीट्रिक टन उत्पादन और 92 लाख रोजगार	क्षेत्र का ग्रामीण महत्व बढ़ा है, पर स्थानीय परिणामों में विविधता है।

टिप्पणी: सभी आँकड़े संबंधित स्रोतों के प्रकाशित निष्कर्षों से लिए गए हैं; वे अपने-अपने अध्ययन क्षेत्र और नमूने तक सीमित हैं।

11. अध्ययन की पद्धति

11.1 शोध अभिकल्प: इस अध्ययन में द्वितीयक स्रोतों पर वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक शोध किया गया है। यह सिर्फ अध्ययनों की सूची देने के साथ-साथ उनके परिणामों को सामाजिक परिवर्तन के साझा आयामों में व्यवस्थित करना और प्रमाणों के बीच अंतर, समानता और सीमाओं की आलोचनात्मक व्याख्या करना भी चाहता है।

11.2 स्रोत-चयन: स्रोत-चयन का समय 2020 से 2025 था। इसमें क्षेत्रीय सामाजिक-आर्थिक अध्ययन, महिला सशक्तिकरण पर अनुभवजन्य शोध, केंद्रीय रेशम बोर्ड और भारत सरकार के योजना-दस्तावेज और रेशम अर्थशास्त्र और सततता से संबंधित समीक्षा-लेख शामिल हैं। प्राथमिकता उन स्रोतों को दी गई जिनमें प्रकाशन वर्ष, लेखक, अध्ययन क्षेत्र, पद्धति और स्थायी पहचान संख्या या आधिकारिक प्रकाशन विवरण उपलब्ध था।

11.3 विश्लेषण की प्रक्रिया: प्रत्येक स्रोत से अध्ययन क्षेत्र, नमूना, आजीविका-प्रभाव, महिला भागीदारी, निर्णय-क्षमता, प्रशिक्षण, बाजार, जोखिम और नीति-संबंधी निष्कर्ष प्राप्त किए गए। इसके बाद परिणामों को छह क्षेत्रों में विभाजित किया गया: आय, रोजगार, लैंगिक परिवर्तन, मानवीय विकास, सामाजिक प्रतिष्ठा और संस्थागत बाधा। विभिन्न अध्ययनों के विभिन्न परिणामों को ध्यान में रखकर व्याख्या की गई।

11.4 विश्वसनीयता और सीमाएँ: अध्ययन ने किसी परिवार के बारे में कोई नया प्राथमिक दावा नहीं किया है। संख्यात्मक नतीजे प्रकाशित स्रोतों तक सीमित हैं। क्षेत्रीय अध्ययनों के संकेतक और नमूने अलग-अलग हैं, इसलिए प्रतिशतों को राष्ट्रीय औसत से नहीं जोड़ा गया। बहुत से अध्ययन अनुप्रस्थ प्रकृति पर हैं; वे रेशम उत्पादन और सामाजिक परिस्थितियों के बीच संबंध को दिखाते हैं, लेकिन दीर्घकालिक कारणता को पूरी तरह से नहीं बताते।

महिलाओं के समय-उपयोग, आय पर नियंत्रण, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य परिणामों पर तुलनीय अनुगामी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

12. विश्लेषण और चर्चा

12.1: आर्थिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का आधार है; पूर्ण परिणाम नहीं, प्रमाणों का समेकित विश्लेषण बताता है कि आय परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का प्रारंभिक माध्यम है। परिवारों को नियमित नकद आय उपभोग, शिक्षा और स्वास्थ्य में विकल्प देती है; लेकिन किस सदस्य को यह विकल्प मिलेगा, यह आय, स्थिरता और नियंत्रण से निर्धारित होता है। सामाजिक प्रभाव सीमित रहेगा अगर आय ऋण-चुकौती या उत्पादन-नुकसान में समाप्त हो जाएगी। यही कारण है कि उत्पादकता कार्यक्रम को मूल्य-जोखिम और धन की सुरक्षा से जोड़ना चाहिए। होसामनी और अन्य, २०२०; Hoganmode, 2023) 12.2 कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के अध्ययन में महिला श्रम की दृष्टि और महिला अधिकार का अंतर दिखाता है: महिलाएँ उत्पादन में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनका सशक्तिकरण सूचकांक अनुमानित स्तर से कम हो सकता है। इसका कारण यह है कि संसाधन पर अधिकार और श्रम का योगदान अलग-अलग संस्थागत व्यवस्थाएँ हैं। श्रम सामाजिक शक्ति में बदलता है जब महिलाओं को भुगतान, बैंकिंग, बिक्री और संगठनात्मक नेतृत्व में स्थान मिलता है। रॉय एवं रॉय मुखर्जी, 2020; Madhu et al., 2023) 12.3 परिवार के निकट नौकरी: महिलाओं, वृद्धों और सीमित गतिशीलता वाले परिवारों के लिए अवसर और समय-दबाव समान हैं। साथ ही घर और कार्यस्थल की सीमा मिटने से कार्य घंटे अदृश्य हो सकते हैं। महिलाएँ घरेलू काम, देखभाल और कीटपालन करती हैं, जो आर्थिक भागीदारी के बावजूद अवकाश और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। इसलिए, समय-उपयोग को सामाजिक लाभ की गणना में अनिवार्य संकेतक बनाना चाहिए। रॉय एवं रॉय मुखर्जी, 2020; Hamid and Fatimah, 2025)

12.4 संस्थागत पहुँच परिवर्तन की मध्यस्थता

असम में प्रशिक्षण की सीमित पहुँच, बिहार में शिक्षा और गतिशीलता के लिए बाधाएँ और पश्चिम बंगाल में बाजार और संसाधन संबंधी समस्याएँ बताती हैं कि परिवार की मेहनत अकेले पर्याप्त नहीं है। सामाजिक परिणामों के मध्यस्थ हैं गुणवत्तापूर्ण बीज, रोग-परीक्षण, विस्तार सेवा, वित्त और बाजार। इस बहुआयामी आवश्यकता को सिल्क समग्र-2 में अनुसंधान, प्रशिक्षण, तकनीक हस्तांतरण, बाजार विकास और लाभार्थी-उन्मुख हस्तक्षेपों के साथ आधिकारिक रूप से स्वीकृत किया गया है। (Central Silk Board, 2022; हतीबरुआ, 2022 में; 12.5 सामाजिक परिवर्तन क्षेत्र-विशिष्ट और असमान है (Bhattacharya et al., 2020)

भूमि, पर्यावरण, संस्कृति और बाजार, शहतूत-प्रधान दक्षिण भारत, तसर-आधारित आदिवासी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल की पारंपरिक मूल्य-श्रृंखला और बिहार के महिला-केंद्रित घरेलू कार्य से अलग हैं। यही कारण है कि एक ही नीति-योजना सभी क्षेत्रों में समान प्रभाव नहीं देगी। विकेंद्रीकृत योजना स्थानीय पोषक वृक्ष, उत्पादन चक्र, सामाजिक समूह और बाजार संरचना के अनुरूप होनी चाहिए। मैरी, 2021; Central Silk Board, 2024) 12.6 संकट-सहनशीलता को बदलाव का मुख्य सूचक मानना चाहिए

महामारी ने दिखाया कि उत्पादन से प्राप्त सामाजिक लाभ खतरे में पड़ जाते हैं जब बाजार और परिवहन बंद हो जाते हैं। दीर्घकालिक परिवर्तन का बेहतर संकेतक यह है कि परिवार रोग, खराब चक्र, जलवायु परिवर्तन या मूल्य-पतन के बाद बिना संपत्ति बेचे और बच्चों की शिक्षा रोके कितनी जल्दी उबरता है। इसलिए उत्पादन की तुलना में बचत, बीमा, उत्पादक समूह और बहु-आय स्रोत उतने ही महत्वपूर्ण हैं। (घोणमोडे, वर्ष 2023; (अल्टमैन और फैरेल, 2022)

तालिका 3. प्रमुख बाधाएँ और नीतिगत समाधान

बाधा	परिवार पर प्रभाव	प्राथमिक समाधान	सामाजिक परिणाम का संकेतक
मूल्य-अस्थिरता	आय और ऋण-चुकोती में अनिश्चितता	पारदर्शी नीलामी, दैनिक मूल्य सूचना, सामूहिक बिक्री	शुद्ध आय की स्थिरता
गुणवत्ताहीन बीज/रोग	पूरा उत्पादन चक्र विफल	प्रमाणित बीज, स्थानीय रोग-परीक्षण और त्वरित परामर्श	चक्र-विफलता में कमी
प्रशिक्षण की कमी	कम उत्पादकता और तकनीकी निर्भरता	व्यावहारिक, चरणबद्ध और स्थानीय भाषा प्रशिक्षण	तकनीक अपनाने की दर
महिला समय-गरीबी	दोहरा कार्यभार और स्वास्थ्य जोखिम	कार्य-विभाजन, उपकरण, बाल-देखभाल और महिला समूह	समय पर नियंत्रण
पूँजी की कमी	कम पैमाना और महंगा ऋण	सरल ऋण, समूह वित्त और बीमा	ऋण-भार और परिसंपत्ति-निर्माण
कम मूल्य-संवर्धन	कोकून स्तर पर सीमित आय	रीलिंग, कताई, डिजाइन और प्रत्यक्ष विपणन	मूल्य-श्रृंखला में परिवार की हिस्सेदारी

स्रोत: केंद्रीय रेशम बोर्ड (2022), हतीबरुआ (2022), घोनमोडे (2023), मधु एवं अन्य (2023) तथा चयनित समीक्षाओं का संश्लेषण

13. पहला प्रमुख निष्कर्ष रेशम उत्पादन ग्रामीण परिवारों को कृषि और गैर-कृषि आय के बीच एक पुल बनाता है और छोटे-छोटे अंतराल में पैसे की आपूर्ति कर सकता है।

यह क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उत्पादन और रोजगार क्षमता है, लेकिन रेशम की प्रकृति, बाजार और संस्थागत पहुँच स्थानीय सामाजिक परिणामों को प्रभावित करते हैं।

महिलाओं की श्रम-भागीदारी व्यापक है, लेकिन उनका सशक्तिकरण तभी होता है जब उनके अधिकार आय, संपत्ति, बाजार और निर्णय पर बढ़ें।

परिवार के निकट रोजगार में गतिशीलता के लिए बाधाएं कम होती हैं, लेकिन यह महिलाओं के दोहरे कार्यभार को बढ़ा सकता है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन-स्तर पर लाभों का मुख्य स्रोत आय की नियमितता और महिला आय-नियंत्रण है; अभी भी इनके दीर्घकालिक कारणात्मक प्रमाण कम हैं।

सामाजिक परिवर्तन के मुख्य मध्यस्थ हैं प्रशिक्षण, रोग-मुक्त बीज, विस्तार सेवा, कार्यशील पूँजी और पारदर्शी बाजार।

परिवार की प्रगति को मूल्य-पतन, महामारी, परिवहन अवरोध, बीमारी और जलवायु परिवर्तन उलट सकते हैं।

सामुदायिक और सहकारी संस्थाएँ केवल बिक्री के लिए नहीं हैं; वे नेतृत्व, जानकारी और सामुदायिक प्रतिष्ठा के मंच भी बन सकते हैं।

आजीविका नीतियों को तसर जैसे वन-आधारित प्रणालियों में संसाधन अधिकार, जैव-विविधता और आदिवासी ज्ञान के साथ जोड़ना चाहिए।

रेशम विकास को उत्पादन की मात्रा से नहीं, बल्कि शुद्ध आय, जोखिम-सहनशीलता, महिला अधिकार, निरंतर शिक्षा और सामाजिक सहभागिता से मूल्यांकन करना चाहिए।

14. मार्गदर्शन परिवार-केंद्रित आधाररेखा: योजना शुरू होने से पहले भूमि, आय, ऋण, बच्चों की शिक्षा, बाजार-दूरी, प्रशिक्षण-स्थिति और महिला समय-उपयोग की आधार रेखा बनाई जाए।

- प्रत्यक्ष महिला भुगतान: योजना सहायता और कोकून बिक्री का भुगतान महिला या संयुक्त खाते में किया जाए; पालन-कक्ष और उपकरण पर संयुक्त स्वामित्व को प्रोत्साहित करें।
- क्षेत्रीय तकनीकी सेवा: ग्राम-समूह स्तर पर प्रशिक्षित सेवा-प्रदाता, रोग-जाँच, तापमान-आर्द्रता परामर्श और आपात प्रतिक्रिया प्रदान करें।
- मूल्यवृद्धि और बाजार में सुधार: पारदर्शी कोकून परीक्षण, स्थानीय नीलामी, सामूहिक परिवहन, बहु-खरीदार प्रणाली और वास्तविक समय मूल्य जानकारी बनाएँ।
- जोखिम भत्ता: रोग और जलवायु जोखिम बीमा, ब्याज सहायता और संकट-कालीन पुनर्भुगतान स्थगन व्यवस्था उत्पादन चक्र के अनुरूप होनी चाहिए।
- मूल्य की वृद्धि: उत्पादक परिवारों को रीलिंग, कताई, डिजाइन, प्राकृतिक रंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और प्रत्यक्ष बिक्री में प्रशिक्षण दिया जाए।
- सर्वव्यापी प्रशिक्षण: महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सीमांत किसानों को समय और स्थान पर अनुकूल प्रशिक्षण; यात्रा सहायता और बाल-देखभाल की सुविधा दी जाए।
- समूह का नेतृत्व: पारदर्शी लेखा, नियमित सामाजिक लेखा-परीक्षण, क्रमिक नेतृत्व परिवर्तन और महिलाओं का वास्तविक प्रतिनिधित्व उत्पादक समूहों में सुनिश्चित होना चाहिए।
- बाल शिक्षा और संरक्षण: बाल श्रम को रोकने के लिए परिवार-आधारित श्रम प्रणाली में बच्चों की स्कूल उपस्थिति की निगरानी की जाए।
- परिणामों पर निर्भर मूल्यांकन: महिला की निर्णय-क्षमता, शुद्ध आय, ऋण-भार, बचत, शिक्षा की निरंतरता और संकट से उबरने की अवधि को उत्पाद और लाभार्थी संख्या के साथ मापा जाए।

15. निष्कर्ष:

रेशम उत्पादन भूमि, श्रम, कौशल और स्थानीय उद्यम को एक निरंतर मूल्य-श्रृंखला में जोड़ने से ग्रामीण परिवारों में सामाजिक परिवर्तन की पर्याप्त संभावना है। उपलब्ध प्रमाण बताते हैं कि इससे स्थानीय रोजगार, महिला भागीदारी, आय-विविधीकरण और सामुदायिक संपर्क बढ़ सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक प्रतिष्ठा और निर्णय-क्षमता में सुधार इन बदलावों से होता है। (Central Silk Board, 2024; (अल्टमैन एवं फैरेल, 2022) लेकिन संस्थागत अंतर वास्तविक परिवर्तन से कल्पना के बीच है। प्रमाणित बीज और तकनीकी सेवा देना, किसानों को

बाजार-मूल्य के जोखिम से बचाना, महिला श्रम को आय और अधिकार में बदलना और कमजोर परिवारों को धन तक समान पहुँच देना आवश्यक है। Karnataka और West Bengal के परिणामों से स्पष्ट होता है कि अधिक महिला श्रम के बावजूद सशक्तिकरण अधूरा रह सकता है। महामारी-काल का अनुभव भी दिखाता है कि बाजार-सुरक्षा के बिना आय-लाभ अस्थिर होता है। रॉय एवं रॉय मुखर्जी, 2020; Madhu and others, 2023; (घोनमोडे, 2023) इसलिए, रेशम नीति का लक्ष्य केवल अधिक कच्चा रेशम और कोकून उत्पादन नहीं होना चाहिए। उसे परिवार की शुद्ध आय, महिला का संसाधन-अधिकार, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य-सुरक्षा, स्थानीय संस्थाओं और संकट-सहनशीलता को समान महत्व देना चाहिए। रेशम उत्पादन ग्रामीण परिवारों के लिए स्थायी सामाजिक गतिशीलता का माध्यम बन सकेगा जब उत्पादन सहायता, सामाजिक सुरक्षा, लैंगिक न्याय और स्थानीय मूल्य-संवर्धन को एक साथ मिलाया जाएगा।

संदर्भ सूची

नोट: संदर्भ 2020–2025 की समय-सीमा तक सीमित हैं। सत्यापन की सुविधा के लिए प्रकाशन-शीर्षक और स्थायी पहचान-संख्या मूल रूप में रखी गई हैं।

Ahmad, R., & Fatima, S. (2025). Socio-Economic Analysis of Women's Participation in Silk Industry in Bihar. *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science*, 6(6), 1318–1323. <https://doi.org/10.38142/ijesss.v6i6.1537>

Altman, G. H., & Farrell, B. D. (2022). Sericulture as a sustainable agroindustry. *Cleaner and Circular Bioeconomy*, 2, 100011. <https://doi.org/10.1016/j.clcb.2022.100011>

Bhattarcharjya, D., Alam, K., Bhuimali, A., & Saha, S. (2020). Status, potentials, constraints and strategies for development of sericulture farming system in West Bengal state of India (review). *Bulgarian Journal of Agricultural Science*, 26(4), 709–718. <https://www.agrojournal.org/26/04-01.pdf>

Central Silk Board. (2022). Silk Samagra-2: Standard operating procedure and guidelines for implementation of the Central Sector Scheme during 2021–22 to 2025–26. Ministry of Textiles, Government of India. https://csb.gov.in/sites/default/files/what_s_new/files/Silk-Samagra-2-Booklet-Hindi_English-118-pages-2-5-2022.pdf

Central Silk Board. (2024). Functioning of Central Silk Board and performance of Indian silk industry (As on 1 January 2024). Ministry of Textiles, Government of India. <https://csb.gov.in/sites/default/files/downloads/Note-On-Sericulture-Jan-2024-Eng.pdf>

Ghonmode, S. V. (2023). Influence of Covid-19 peak period on sericulture farmers, reelers, weavers and traders. *Current Agriculture Research Journal*, 11(1), 212–218. <https://doi.org/10.12944/CARJ.11.1.18>

Hatibaruah, D. (2022). Socio-economic analysis among the farmers engaged in sericulture practices in Jorhat District of Assam, India. *Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology*, 40(3), 36–40. <https://doi.org/10.9734/ajaees/2022/v40i330856>

- Hosamani, V., Yalagi, M., Sasvihalli, P., Hosamani, V., Nair, K. S., Harlapur, V. K., Hegde, C. R., & Mishra, R. K. (2020). Constraints and economics of sericulture: A review. *International Journal of Chemical Studies*, 8(1), 746–750. <https://doi.org/10.22271/chemi.2020.v8.i1k.8353>
- Madhu, D. M., Sinha, D. K., Singh, K. M., Kumari, T., Singh, R. P., Kumari, S., & Ahmad, N. (2023). Achieving sustainable development goal by empowering women through mulberry silk production in Karnataka, India. *Agriculture Association of Textile Chemical and Critical Reviews Journal*, 1–6. <https://doi.org/10.58321/AATCCReview.2023.11.01.01>
- Mishra, P. (2021). A study on the status and prospects of Tasar sericulture industry and its impact on tribal lives in Jharkhand. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*, 9(9), 1773–1777. <https://doi.org/10.22214/ijraset.2021.38250>
- Reddy, Y. P., & Parasuramudu, M. (2024). Role of sericulture in the Indian economy. *Journal for Research in Applied Sciences and Biotechnology*, 3(4), 107–116. <https://doi.org/10.55544/jrasb.3.4.13>
- Roy, C., & Roy Mukherjee, S. (2020). A study on productivity empowerment of women intensive sericulture sector of West Bengal. *Productivity*, 61(2), 169–179. <https://doi.org/10.32381/PROD.2020.61.02.5>